



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 295 राँची, शुक्रवार 11 वैशाख, 1937 (श०)
1 मई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 अप्रैल, 2015

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, गढ़वा का पत्रांक-1227/गो0, दिनांक 02 जून, 2011 एवं पत्रांक-198/स्था0, दिनांक 06 मार्च, 2013
2. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-539/गो0, दिनांक 06 मार्च, 2010
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-4102, दिनांक 21 जुलाई, 2011, पत्रांक-10092, दिनांक 31 अगस्त, 2012, पत्रांक-8026, दिनांक 08 अगस्त, 2014 एवं स्मार पत्रांक-9334, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 एवं संकल्प संख्या-4884, दिनांक 07 जून, 2013 तथा संकल्प संख्या-4884, दिनांक 07 जून, 2013
4. श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-168, दिनांक 28 मार्च, 2014 एवं पत्रांक-189, दिनांक 11 अप्रैल, 2014

संख्या: 5/आरोप-1-417/2014 का.-3977 -- श्री महावीर सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-549/03, गृह जिला- नवादा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा, प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनियाँ एवं भण्डरिया के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-1227/गो0, दिनांक 02 जून, 2011 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. इंदिरा आवास निर्माण में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने, अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रखने, चिनियाँ प्रखण्ड के बिलैतीखैर पंचायत अंतर्गत ग्राम राजबास के 18 इंदिरा आवास लाभुको के निर्गत प्रति लाभुक रु० 17,500/- प्रखण्ड नाजिर रामाधार राम एवं पंचायत सेवक श्री धर्मदेव ठाकुर द्वारा श्री अशोक यादव पिता हरिहर यादव ग्राम राजबास के साथ मिलकर राशि का गबन करने में संलिप्तता का आरोप ।

2. चिनियाँ प्रखण्ड (तत्कालीन प्रभार वाला प्रखण्ड) में इंदिरा आवास के निर्माण में पर्याप्त रुचि नहीं लेने के फलस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी तथा बड़ी संख्या में योजना लंबित रखने का आरोप ।

3. रमकंडा प्रखंड (मूल प्रभार) में भी इंदिरा आवास निर्माण में पर्याप्त रुचि नहीं लेने के कारण निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में परस्पर विरोधाभास का आरोप ।

4. भंडरिया प्रखंड (तत्कालीन प्रभार वाला प्रखंड) में लक्ष्य के विरुद्ध इंदिरा आवास योजना नहीं लिया जाना तथा राशि खर्च नहीं करने का आरोप ।

5. इनका पदस्थापन रमकंडा प्रखण्ड में है, लेकिन ये अनधिकृत रूप से गढ़वा प्रखण्ड परिसर में नवनिर्मित सरकारी आवासीय भवन में विगत डेढ़ वर्षों से रहते हुए सरकारी मकान भत्ता की निकासी भी कर रहे हैं तथा देय किराया भी जमा नहीं कर रहे हैं ।

6. ये जब भी अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय से बाहर जाते हैं, कभी भी ससमय वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि एक-दो दिन पश्चात् मुख्यालय वापस आते हैं, जिससे सरकारी कार्य के ससमय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

7. सरकारी कार्य ससमय निष्पादन में इनके द्वारा रुचि नहीं दिखलाई जाती है और न ही माँगे गए प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो इनके कार्यशैली में शिथिलता का परिचायक है।

8. कूप निर्माण हेतु ग्रामीण जनता से प्राप्त आवेदन पत्र पर मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्रवाई न करने तथा कूप के 19 लाभुकों से पाँच-पाँच हजार रुपये अवैध राशि की माँग का आरोप तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण नहीं देने तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप ।

9. भंडरिया प्रखंड के इनके प्रभार अवधि में अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के खाद्यान्न में हुई कालाबाजारी के प्रकाशित मामले में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-623/ गो0, दिनांक

22 मार्च, 2011 से तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिनांक 25 मार्च, 2011 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु इनके द्वारा आज तक वस्तुस्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होना, इनकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संलिप्तता की ओर इंगित करता है। इनके स्पष्टीकरण के अभाव में विषयाधीन कार्यवाही अब तक अवरूद्ध एवं लंबित होने का आरोप ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4102, दिनांक 21 जुलाई, 2011 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री सिंह के पत्रांक-2474, दिनांक 08 सितम्बर, 2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-198/स्था0, दिनांक 06 मार्च, 2013 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर दिया गया है। फलतः विभागीय संकल्प संख्या-4884, दिनांक 07 जून, 2013 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा के पत्रांक-168, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

एक अन्य मामले में श्री सिंह के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-539/गो0, दिनांक 06 मार्च, 2010 के द्वारा आरोप प्रपत्र-‘क’ में प्राप्त है, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. आर0ई0ओ0 रोड से वासुदेव के घर तक मिट्टी मोरम ग्रेड-1 सड़क निर्माण (यो0 अभि0 सं0- 53/2008-09):-

समिति के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि इस योजना स्थल के अगल-बगल में मिट्टी कटाई का कोई साक्ष्य नहीं पया गया। काफी दिनों से बंद पड़े तथा प्राक्कलन की विशिष्टियों के विरुद्ध सड़क निर्माण में कही-कही प्रयुक्त किये गये मिट्टी के संबंध में जाँच दल के द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि किसी दूसरे जगह से ट्रैक्टर से मिट्टी लाकर भर दिया गया है। इस योजना अभिलेख में संलग्न मस्टर रोल के संधारण और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया भी संदेहास्पद पाई गई है, क्योंकि मस्टर रोल में तिथि, कार्य दिवस अंकित नहीं पाई गई तथा पहचानकर्ता/सत्यापनकर्ता का कही हस्ताक्षर अंकित नहीं पया गया। जाँच दल के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उपलब्ध मस्टर रोल के इन्दराज से यह भी स्पष्ट नहीं है कि मजदूरी का भुगतान बैंक/ डाकघर के माध्यम से किया गया है ।

2. बंशी रविदास के घर से मुख्य पथ में मिट्टी मोरम ग्रेड-1 सड़क का निर्माण (यो0 अभि0 सं0- 08/2008-09):-

योजना की स्वीकृति राशि 11,50,500.00 रुपये के विरुद्ध जाँच के समय तक योजना कार्य में किये गये भुगतान मो0 8,69,752/- रुपये के संबंध में जाँच समिति के द्वारा यह प्रतिवेदन किया गया

है कि स्थानीय पूछताछ से यह ज्ञात हुआ है कि इसी कार्य स्थल में 2-3 वर्ष पूर्व पंचायत की योजना से भी मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। इससे संबंधित अभिलेख की माँग किये जाने पर आपने जाँच दल का सहयोग नहीं दिया। किये गये कार्य की गुणवत्ता के संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है तथा इस कार्य स्थल में भी मिट्टी किसी दूसरे स्थल से ट्रैक्टर या अन्य माध्यम के द्वारा लाकर भरी गई प्रतीत होती है। जाँच के समय मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल की जो प्रति उपलब्ध कराई गई उसके स्वरूप तथा आवश्यक छानबीन के बाद यह निष्कर्ष दिया गया है कि मस्टर रोल प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है।

3. खगड़ा नाला में रवि मण्डल के खेत के सामने चैकडैम का निर्माण (यो0 अभि0 सं0-01/2006-07):-

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 10,97,600.00 रु0 का भुगतान के संबंध में संधारित मस्टर रोल के संबंध में जाँच दल के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मस्टर रोल फर्जी प्रतीत होता है, क्योंकि सभी अंगूठे का निशान एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं तथा भुगतान का माध्यम भी बैंक/डाकघर नहीं है।

4. वासुदेव मण्डल के घर से कोमल मण्डल के घर तक मिट्टी-मोरम सड़क का निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 3,82,000/-रु० के विरुद्ध 2,44,981/- रु० के भुगतान के संबंध में संधारित मस्टर रोल के संबंध में जाँच दल के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मस्टर रोल फर्जी प्रतीत होता है तथा भुगतान का माध्यम भी बैंक/डाकघर नहीं है।

5. पूरन मण्डल के घर से डेगन आहार तक मिट्टी मोरम ग्रेड-1 सड़क का निर्माण (यो0 अभि0 सं0-027/2008-09):-

जाँच दल के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिया निर्माण का कार्य प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है तथा घटिया सामग्री के उपयोग के साथ-साथ निर्माण कार्य भी असंतोषजनक हैं। सड़क निर्माण में मिट्टी कटाई/भराई के संबंध में यह प्रतिवेदित किया गया है कि मिट्टी कहीं बाहर से लाकर भर दिया गया प्रतीत होता है, क्योंकि काग्र स्थल के आसपास मिट्टी कटाई का कोई संकेत नहीं पाया गया है। अभिलेख में संलग्न मस्टर रोल के संधारण के स्वरूप के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम दृष्टया यह संदेहास्पद प्रतीत होता है तथा भुगतान के संबंध में किसी बैंक या डाकघर का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-10092, दिनांक 31 अगस्त, 2012 एवं अनुवर्ती स्मार-पत्रों द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी परन्तु श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित न कर कतिपय अभिलेखों की माँग की जाती रही। फलतः विभागीय संकल्प संख्या-4884, दिनांक 07 जून, 2013 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा,

सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा के पत्रांक-189, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, श्री सिंह के उभय स्थानों (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा, प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनियाँ एवं भण्डरिया तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह) के पदस्थापन काल के प्रमाणित आरोपों हेतु काल-वेतन मान में निम्नतर स्तर पर अवनति का दण्ड प्रस्तावित किया गया। विभागीय पत्रांक-8026, दिनांक 08 अगस्त, 2014 एवं स्मार पत्रांक-9334, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक-1445, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः श्री सिंह पर काल-वेतन मान में निम्नतर स्तर पर अवनति का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।
